फा.सं.जेड-14014/2/2020-जीसी (ई-3010062)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 14.07.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: जून, 2020 के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रमुख कार्यकलापों एवं महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. के संदर्भ में और जून, 2020 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1) भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2) भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3) भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4) उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5) सभी सचिव, भारत सरकार।
6) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7) तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा जून, के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों और लिए गए 2020 महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के दो एसआरओ में 15 जून, 2020 को राष्ट्रीय व्यापक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) को शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत भू-नक्शा अपनाने के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु 08 जून और 19 जून, 2020 को राजस्व सचिव, गोवा सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का आयोजन किया गया था।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत 2020-21 हेतु 238.65 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में जून, 2020 में 23.85 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

विभाग ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 02.06.2020, 17.06.2020 और 26.06.2020 को आयोजित की गईं तीन वीडियो कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी। कोविड-19 के बावजूद, इस तिमाही के दौरान 467 वाटरशेड विकास परियोजनाएं पूरी की गईं। अब तक कुल 6382 {8214 (स्वीकृत)-1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} में से 3709 वाटरशेड विकास परियोजनाएं पूरी की गईं हैं। 2020-21 के लिए 2000 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में जून, 2020 में 88.05 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

विश्व बैंक ने 09.06.2020 को आरईडबल्यूएआरडीएस परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए साझेदार राज्यों और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक का आयोजन किया। राज्यों ने बजट लाइन्स के सृजन, राज्य स्तरीय पीएमयू और अन्य शुरुआती कार्यकलापों के बारे में सूचित किया। भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पीएमयू स्थापित करने संबंधी प्रगति के बारे में अवगत कराया।

*****